

1	2	3	4	5
2601	नई मद	माल का वर्णन	--	अयस्क, धातु मल तथा राख जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट न हो ।
2601	नई मद	प्रति अदायगी की न्यून दर	--	दर अलग-अलग विनिर्माता/निर्यातकर्ता से आवेदन प्राप्त होने पर प्रति अदायगी नियमों के अनुसार नियत की जाएगी ।
2701	1001	माल का वर्णन	पेट्रोलियम उत्पाद जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट न हों ।	खनिज ईंधन, खनिज तेल और निधारकर कर प्राप्त किए जाने वाले उनके उत्पाद विटामिन पदार्थ, खनिज मोम जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट न हो ।
28	--	अध्याय शीर्ष के तहत वर्णन	अकार्बनिक रसायन, कीमती धातुओं अथवा दुर्लभ धातुओं के कार्बनिक अथवा अकार्बनिक मिश्रण रेडियो क्रियाशील धातु अथवा आइसोटोप हों ।	अकार्बनिक रसायन; कीमती धातुओं अथवा दुर्लभ धातुओं के कार्बनिक अथवा अकार्बनिक मिश्रण रेडियो क्रियाशील धातु अथवा आइसोटोप हों ।
2801	1101	माल का वर्णन	अकार्बनिक रसायन जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट न हों	अकार्बनिक रसायन; कीमती धातुओं अथवा दुर्लभ धातुओं के कार्बनिक अथवा अकार्बनिक मिश्रण रेडियो क्रियाशील धातु अथवा आइसोटोप हों जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट न हों ।
शून्य	1186 (क)	पृ. 28 पर उपक्रमांक सं. के तहत विवरण	शून्य	उपक्रमांक सं. 2806
2901	1101 और 1201	माल का वर्णन	कार्बनिक रसायन और रसायनिक उत्पाद जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट न हों	कार्बनिक रसायन जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट न हों ।
2905	1305	माल का वर्णन	क्लोरोप्रोपोमाइड	क्लोरोप्रोपोमाइड
3003	1203 (iii)	विनिधान	8.95 रु. सी.शु.	7.50 रु. सी.शु.
31	1203 (iv)	विनिधान टिप्पणी के नीचे	71.20 पैसे सी.शु. केवल पैकिंग सामग्री के लिए प्र.अ. लागू होगी ।	60.25 रु. सी.शु. हटा दिया गया है ।
3101	नई मद	माल का वर्णन	--	खाद, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट हो ।
3101	नई मद	प्रति अदायगी की दर	--	दर अलग-अलग विनिर्माता/निर्यातकर्ता से आवेदन प्राप्त होने पर प्रति अदायगी नियमों के अनुसार नियत की जाएगी ।
32	--	अध्याय शीर्ष का वर्णन	रंजक, वर्णक और रंगाई का अन्य सामान पेंट और वार्निश और स्याही	ट्रेनिंग अथवा रंजक सान्द्र टानिस और उनके डेरिवेटिव रंग वर्णक और अन्य रंजक सामग्री; पेंट और वार्निश पुटीन और अन्य मस्तग्री स्याही
3201	1301	माल का वर्णन	संश्लिष्ट कार्बनिक रंजक द्रव्य रंजक मध्य-वर्ती द्रव्य, वर्णक रंजक द्रव्य और रंग लैक्स ; जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट न हो, वर्णक रंग, पेंट अनेमल, वार्निश लैक्स, मुद्रण स्याही और लेखन स्याही जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट न हो ।	ट्रेनिंग अथवा रंजक सान्द्र टानिस और उनके डेरिवेटिव रंग, वर्णक और अन्य रंजक सामग्री पेंट और वार्निश, पुटीन और अन्य मस्तग्री स्याही जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट न हो ।
3301	1501	माल का वर्णन	सुगन्धित तेल, सुगन्धवाली सामग्री अगर बस्तियां, प्रसाधन सामग्री पालिश और सफाई निमित्तियां जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट न हों ।	सुगन्धित तेल, रसिन ऐड्स, सुगन्ध सामग्री, सोन्दर्य अथवा प्रसाधन विनिमित्तियां जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट न हो ।

दिए गए हैं :—

1. श्री ईश्वरी प्रसाद, सेवा-निवृत्त सचिव,  
भारत सरकार --अध्यक्ष
2. श्री आर० के० नरूला, अवर सचिव, श्रम मंत्रालय --सदस्य
3. श्री ए० ए० प्रसाद, प्रबंधक (आई० आर०-एल०),  
भारतीय खाद्य निगम --सदस्य
4. श्री सत्य नारायण गुप्त, अवर सचिव,  
खाद्य प्रापण और वितरण विभाग --सदस्य-सचिव  
एवं समन्वयकर्ता

5. समिति के विचारणीय विषय निम्नानुसार होंगे :—

- (1) भारतीय खाद्य निगम के पंजाब में स्थित सभी डिपुओं के संबंध में कार्यभार से संबंधित अब तक एकत्र और संकलित किए गए आंकड़ों की जांच करना ।
- (2) भारतीय खाद्य निगम से 1991-92 से 1993-94 तक के तीन वर्षों के शेष आंकड़े, यदि कोई हों, प्राप्त करना और उनकी जांच करना ।
- (3) समिति द्वारा निर्धारित किए गए मानदण्डों के आधार पर यह सिफारिश करना कि क्या कुछ डिपुओं में पहले से लागू "कोई कार्य नहीं कोई वेतन नहीं" की प्रणाली न्यायसंगत है और क्या ठेका श्रम (विनियम और उत्पादन) अधिनियम, 1970 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों को ध्यान में रखते हुए तथा उपर्युक्त आंकड़ों के आकलन/जांच के आधार पर पंजाब में भारतीय खाद्य निगम के शेष डिपुओं में भी यह प्रणाली लागू की जा सकती है ।
- (4) समिति के कार्य से जुड़े किसी अन्य मामले को देखना, चाहे वह मामला उसे किसी एजेंसी/प्राधिकरण/यूनियन ने भेजा हो या न भी भेजा हो और इस संबंध में सिफारिशें देना ।
- (5) समिति 30-11-1995 तक अपनी रिपोर्ट/सिफारिशों को अन्तिम रूप देगी और उसे/उन्हें सचिव, खाद्य प्रापण और वितरण विभाग को और उसकी प्रतियां सचिव, श्रम मंत्रालय तथा भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी ।

6. समिति सप्ताह में कम से कम एक बैठक करेगी और यदि जरूरी हो तो प्रतिदिन बैठक कर सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसकी रिपोर्ट/सिफारिशें निर्धारित समय के अन्दर सरकार को उपलब्ध हो जाएं । समिति एक मासिक रिपोर्ट सचिव (खाद्य प्रापण और वितरण) को और उसकी प्रतियां सचिव, श्रम मंत्रालय तथा भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी जिसमें समीक्षाधीन अवधि के दौरान उसकी उल्लेखनीय उपलब्धियों का ब्यौरा दिया गया हो ।

7. समिति का मुख्यालय 16-20, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली पर

स्थित भारतीय खाद्य निगम की इमारत में होगा । समिति की रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई की मानीटरिंग खाद्य मंत्रालय में खाद्य प्रापण और वितरण विभाग द्वारा की जाएगी । समिति को अपेक्षित अनुसचिवीय सहायता भारतीय खाद्य निगम द्वारा दी जाएगी ।

8. भारतीय खाद्य निगम द्वारा समिति के अध्यक्ष को उपयुक्त/तयशुदा पारिश्रमिक अदा किया जाएगा । अध्यक्ष के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का खर्च भारतीय खाद्य निगम द्वारा वहन किया जाएगा और समिति के शेष सदस्यों के इन भत्तों का खर्च उन संबंधित विभाग/संगठन द्वारा वहन किया जाएगा जिनसे वे सम्बद्ध हैं ।

9. समिति उस तारी को गठित मानी जाएगी जिस तारीख से समिति के अध्यक्ष कार्यभार शुरू कर लेंगे ।

श्री पी० भट्टी, उप सचिव

## MINISTRY OF FOOD

(Department of Food Procurement & Distribution)

### RESOLUTION

New Delhi, the 7th September, 1995

No. 18011/3/95/FC-3.—The Food Corporation of India (FCI) had introduced in July, 1993 the "Work No-Pay" system for the labourers/workers in 3 depots in Punjab. This system required payment of wages to the labourers/workers directly by the FCI through a three member committee nominated by the representatives of the labourers.

2. This caused resentment among other unions. Consequently thereto the Lal Jhanda FCI Workers and Punjab Palledar Union filed a petition in the Punjab and Haryana High Court pleading for introduction of the same system in the 'Dhuri' depot of FCI also in Punjab. The writ petition was dismissed by the Hon'ble High Court. Thereupon the Unions filed a special Leave Petition (C) No. 15483/94 before the Hon'ble Supreme Court of India against the order of the Punjab & Haryana High Court. The Hon'ble Supreme Court passed the following orders thereon on 27-3-95 :—

"We direct the Union of India through the Secretary, Ministry of Food and Secretary, Ministry of Labour to examine the matter and take a final decision in this respect within 8 weeks from the receipt of this order. We direct that a consolidated decision should be taken in respect of the 140 units including Dhuri unit which are situated in the State of Punjab. We give liberty to the Union of India to seek clarification or

further directions from this Court if necessary."

3. It was felt that 8 weeks time allowed by the Hon'ble Supreme Court was too short to implement the decision of the Hon'ble Court as workload data relating to three years ending 1993-94 was to be collected and evaluated based on certain norms, although the FCI had already been asked/directed to collect and compile the required data. An application seeking extension of time for at least another six months was therefore, filed in the Hon'ble Supreme Court on 16-6-95. The data for three years ending 1993-94 for a majority of Punjab depots have since been collected by the FCI. The data are now to be examined and evaluated.

4. In order to comply with the order of the Hon'ble Supreme Court the Government of India has now decided to constitute a Committee comprising the under-mentioned persons with the terms of reference mentioned in the succeeding para :—

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 1. Shri Ishwari Prasad, Retd. Secretary to the Govt. of India              | —Chairman                          |
| 2. Shri R.K. Narula, Under Secy., Ministry of Labour                       | —Member                            |
| 3. Shri H. L. Prasad, Manager (IR-L), FCI,                                 | —Member                            |
| 4. Shri S.N. Gupta, Under Secy., Deptt. of Food Procurement & Distribution | —Member-Secretary and Coordinator. |

5. The terms of reference of the Committee will be as follows :—

- (1) To sift the data relating to workload collected and compiled so far in respect of all the depots of FCI in Punjab.
- (2) To collect from the FCI the remaining data, if any, for the three years 1991-92 to 1993-94 and to sift the same.
- (3) To recommend on the basis of norms to be prescribed for the Committee whether the system of 'No work No pay' already introduced in some of the depots is justified and whether the same can be extended to the remain-

ing depots of the FCI in Punjab having regard to the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 and the rules made thereunder and based on the evaluation/examination of the data referred to above.

- (4) To look into any other matter incidental to or connected with the work of the committee whether referred to it by any agency/authority/union or not and making recommendations with regard thereto.
- (5) The Committee shall finalise its report/recommendations by 30-11-95 and submit the same to the Secretary, Deptt. of Food Procurement and Distribution with a copy to the Secretary, Ministry of Labour and the Chairman, FCI.
- (6) The Committee shall meet at least once a week and may hold daily meetings, if necessary, so as to ensure that its report/recommendations are available to the Govt. within the stipulated time. The Committee shall also submit a monthly report to the Secretary (FP&D) with a copy to Secretary, Ministry of Labour and the Chairman, FCI highlighting its significant achievements during the period under report.
- (7) The Head Office of the Committee shall be at FCI Building at 16-20, Barakhamba Lane, New Delhi. Monitoring of the follow up action on the report of the Committee shall be done by the Deptt. of Food Procurement & Distribution in the Ministry of Food. Secretarial assistance required by the Committee shall be provided by the Food Corporation of India.
- (8) Suitable/Negotiated remuneration will be paid to the Chairman of the Committee by the Food Corporation of India. Expenditure on account of T.A./D.A. of the Chairman shall be borne by the Food Corporation of India and those of the members of the Committee shall be borne by the respective department/organisation to which they belong.
- (9) The Committee shall be treated to have been constituted from the date the Chairman of the Committee takes over the charge.

G.P. BHATTI, Dy. Secy.

